International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

Original Article

१९१७ से १९३४ के बीच बिहार का ग्रामीण समाज और राष्ट्रीय आंदोलन: आर्थिक असंतोष से राष्ट्रवादी जनसक्रियता तक

नेहा कुमारी
शोध-छात्रा, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार, भारत

Manuscript ID: IJAAR-130418
ISSN: 2347-7075
Impact Factor – 8.141

Volume - 13
Issue - 4
March – April 2026
Pp. 95 - 106

Submitted: 17 Mar. 2026
Revised: 30 Mar. 2026
Accepted: 5 Apr. 2026
Published: 10 Apr. 2026

Corresponding Author:
नेहा कुमारी

Quick Response Code:

Website: https://ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.19970274

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.19970274

सारांश:

प्रस्तुत शोध-पत्र १९१७ से १९३४ के मध्य बिहार के ग्रामीण समाज की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का विश्लेषणात्मक परीक्षण करता है। यह अवधि चम्पारण सत्याग्रह से आरम्भ होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समापन तक विस्तृत है। इतिहास-लेखन की प्रचलित परम्पराएँ, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी अथवा सबाल्टर्न प्रायः ग्रामीण समाज को केवल एक प्रतिक्रियाशील या आज्ञाकारी इकाई के रूप में चित्रित करती हैं। इस शोध-पत्र का केन्द्रीय तर्क यह है कि बिहार का ग्रामीण समाज एक सक्रिय, स्वायत्त और सचेत राजनीतिक अभिकर्ता था, जिसने स्थानीय कृषि-असंतोष को राष्ट्रवादी चेतना में रूपान्तरित कर राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तविक जन-आधारित शक्ति बनाया। सूक्ष्म-इतिहास पद्धति और क्षेत्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह आलेख चम्पारण, शाहाबाद, पटना और पूर्वी बिहार के उदाहरणों से यह प्रमाणित करता है कि आर्थिक शिकायतें किस प्रकार चरणबद्ध ढंग से राजनीतिक भागीदारी और राष्ट्रीय जागरण में परिणत हुईं। यह आलेख बिहार की क्षेत्रीय विविधता को रेखांकित करते हुए एक मौलिक सैद्धांतिक मॉडल 'ग्रामीण चेतना का बहु-स्तरीय मॉडल' प्रस्तुत करता है जो आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करता है।

मुख्य शब्द: बिहार, ग्रामीण समाज, किसान आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, सत्याग्रह, कृषि-राजनीति, औपनिवेशिक भारत।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:
नेहा कुमारी (2026). १९१७ से १९३४ के बीच बिहार का ग्रामीण समाज और राष्ट्रीय आंदोलन: आर्थिक असंतोष से राष्ट्रवादी जनसक्रियता तक. International Journal of Advance and Applied Research, 13(4), 95 - 106. https://doi.org/10.5281/zenodo.19970274

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

प्रस्तावना:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास-लेखन में एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति रही है, उसे मुख्यतः नेताओं, संगठनों और नगरीय अभिजात वर्ग की दृष्टि से समझने की। किन्तु यदि हम पूछें कि यह आंदोलन 'जन-आंदोलन' कैसे बना, तो उत्तर अनिवार्यतः ग्रामीण भारत की ओर ले जाता है। बिहार, जो बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गहरे कृषि-संकट, ज़मींदारी उत्पीड़न और औपनिवेशिक राजस्व-दोहन से ग्रस्त था, इस प्रश्न का सबसे समृद्ध उत्तर प्रस्तुत करता है।

१९१७ में चम्पारण सत्याग्रह के साथ जो यात्रा आरम्भ हुई, वह १९३४ तक के सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिपक्वता को प्राप्त हुई। इन सत्रह वर्षों में बिहार के गाँवों ने केवल आदेशों का पालन नहीं किया, उन्होंने स्वयं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपान्तरित किया। नील-किसानों की पीड़ा ने राष्ट्रवादी संवाद को जन्म दिया; असहयोग की लहर ने ग्रामीण युवाओं को स्वयंसेवक बनाया; और नमक-सत्याग्रह ने लगान-अस्वीकृति के रूप में कृषि-जगत में अभूतपूर्व प्रतिध्वनि उत्पन्न की।

१. शोध-रिक्तता:

प्रचलित राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन गाँधी, नेहरू और कांग्रेस के नेतृत्व को केन्द्र में रखकर ग्रामीण अभिकर्तृत्व को हाशिये पर धकेल देता है। मार्क्सवादी इतिहासकार आर्थिक कारणों को महत्त्व देते हैं, किन्तु राष्ट्रवादी चेतना की स्वायत्त भूमिका को नकारते हैं। सबाल्टर्न अध्ययन-समूह ने किसान स्वायत्तता का उद्घाटन किया, परन्तु बिहार की क्षेत्रीय विविधता को पर्याप्त सैद्धांतिक आधार नहीं दिया। इस प्रकार तीनों प्रमुख धाराएँ आंशिक सत्य को पूर्ण सत्य मान लेती हैं।

२. शोध-प्रश्न:

प्रस्तुत शोध निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है: (१) १९१७–१९३४ की अवधि में बिहार के ग्रामीण समाज की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी का स्वरूप और गहराई क्या थी? (२) क्या यह भागीदारी केवल आर्थिक असंतोष से उत्प्रेरित थी अथवा उसमें स्वतन्त्र राष्ट्रवादी चेतना भी विद्यमान थी? (३) स्थानीय कृषि-शिकायतें किस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीतिक एजेण्डे में रूपान्तरित हुईं? (४) बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जनसक्रियता के स्वरूप में क्या अन्तर थे?

यह शोध-पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि १९१७ से १९३४ के मध्य बिहार के ग्रामीण समाज ने स्थानीय कृषि-असंतोष को सक्रिय रूप से व्यापक राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना में परिणत किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन एक अभिजात नेतृत्व-केन्द्रित संघर्ष से उठकर वास्तविक जन-आधारित राजनीतिक शक्ति बन सका।

इतिहास-लेखन का आलोचनात्मक परीक्षण:

बिहार के ग्रामीण आंदोलनों पर उपलब्ध इतिहास-लेखन को मुख्यतः चार धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न और क्षेत्रीय। प्रत्येक धारा ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान की है, किन्तु प्रत्येक की अपनी सैद्धांतिक सीमाएँ भी हैं।

बिपन चन्द्र ने अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों में राष्ट्रीय आंदोलन को एक एकीकृत, कांग्रेस-नेतृत्व वाले संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

बिपन चन्द्र ने राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस-नेतृत्व वाले एकीकृत संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।[1] उनके विश्लेषण में ग्रामीण भागीदारी संगठनात्मक विस्तार का परिणाम मात्र बन जाती है, न कि एक स्वायत्त राजनीतिक प्रक्रिया। एरिक स्टोक्स ने कृषि-संरचना को निर्धारक तत्त्व माना[2], उनका कार्य आर्थिक कारकों की व्याख्या में महत्त्वपूर्ण है, किन्तु राष्ट्रवादी चेतना के उद्भव की व्याख्या अपूर्ण रहती है। रणजीत गुहा के नेतृत्व में सबाल्टर्न अध्ययन-समूह ने यह स्थापित किया कि किसान अपनी स्वायत्त तर्क-प्रणाली से संचालित होते हैं[3], यह दृष्टिकोण क्रान्तिकारी है, किन्तु बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ जाति, वर्ग और क्षेत्र तीनों आयाम एक साथ काम करते हैं, वहाँ यह अति-सामान्यीकरण का शिकार हो जाता है।

तालिका १: इतिहासकारों के दृष्टिकोण — तुलनात्मक विश्लेषण

इतिहासकार	मुख्य तर्क	सीमाएँ	प्रस्तुत शोध की स्थिति
बिपन चन्द्र	राष्ट्रीय एकता एवं कांग्रेस-नेतृत्व केन्द्रित दृष्टिकोण, कांग्रेस की भूमिका को सर्वोच्च माना	ग्रामीण अभिकर्तृत्व तथा स्थानीय असंतोष को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया।	ग्रामीण सक्रियता को केन्द्र में रखता है।
एरिक स्टोक्स	कृषि-संरचना एवं भूमि-सम्बन्ध आंदोलन के निर्धारक तत्त्व हैं।	राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद का आयाम उपेक्षित रहा।	आर्थिक और राजनीतिक दोनों आयामों का एकीकरण करता है।
रणजीत गुहा	किसानों की स्वायत्त तर्क-प्रणाली, वे अपनी शर्तों पर लड़े।	बिहार की क्षेत्रीय विविधता का अति-सामान्यीकरण।	क्षेत्रीय विभिन्नता को सैद्धांतिक आधार देता है।
ज्ञान प्रकाश	औपनिवेशिक जाति-संरचना एवं श्रम-सम्बन्धों की केन्द्रीयता।	राष्ट्रवादी राजनीति से सम्बन्ध अपर्याप्त।	जाति-आयाम को राष्ट्रवाद से जोड़कर देखता है।

प्रस्तुत शोध इन सभी धाराओं से सहायता लेते हुए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया को केन्द्र में रखा गया है। साथ ही, ग्राम्स्की की 'वर्चस्व' (hegemony) की अवधारणा के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार औपनिवेशिक सहमति का निर्माण हुआ और ग्रामीण प्रतिरोध ने उसे किस प्रकार चुनौती दी।

शोध-पद्धति एवं स्रोत:

१. पद्धतिगत दृष्टिकोण:

यह शोध मुख्यतः सूक्ष्म-इतिहास और क्षेत्रीय तुलनात्मक विश्लेषण की पद्धतियों पर आधारित है। सूक्ष्म-इतिहास की पद्धति विशिष्ट स्थानों, चम्पारण, शाहाबाद, पटना और पूर्णिया, के अनुभवों की गहराई से जाँच का अवसर देती है। साथ ही, तुलनात्मक क्षेत्रीय विश्लेषण यह समझने में सहायक है कि बिहार के विभिन्न भागों में जनसक्रियता के स्वरूप में क्यों अन्तर था।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

सैद्धांतिक उपकरणों में सबाल्टर्न अभिकर्तृत्व, राजनीतिक जनसक्रियता का सिद्धांत और ग्राम्स्की की 'जैविक बुद्धिजीवी' की अवधारणा का उपयोग किया गया है। ग्राम्स्की का 'वर्चस्व' का सिद्धांत यह समझने में सहायक है कि औपनिवेशिक सत्ता ने किस प्रकार ग्रामीण सहमति का निर्माण किया और किसानों ने किस प्रकार इस वर्चस्व को चुनौती दी।

२. प्राथमिक स्रोत:

अभिलेखागार स्रोत: बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना के राजस्व अभिलेख एवं पुलिस रिपोर्ट (१९१७–१९३४)[4]; भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कागज़ात[5]; ज़िला गजेटियर (चम्पारण, शाहाबाद, पटना, पूर्णिया)।

समकालीन समाचार-पत्र: द सर्चलाइट (पटना), अमृत बाज़ार पत्रिका, प्रताप, इनके १९१७–१९३४ के अंकों में ग्रामीण आंदोलनों की विस्तृत रिपोर्टिंग उपलब्ध है।

सरकारी दस्तावेज़: राजस्व बन्दोबस्त रिपोर्टें (१९१०–१९२०); किराया जाँच समिति की रिपोर्टें; पुलिस आसूचना सारांश (PAI)।

चम्पारण और ग्रामीण जनसक्रियता का उद्भव (१९१७–१९२२):

चम्पारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है, किन्तु उसका महत्त्व केवल गाँधी के प्रथम सत्याग्रह के रूप में नहीं है। उसका गहरतर महत्त्व यह है कि उसने पहली बार यह प्रमाणित किया कि एक स्थानीय, विशिष्ट आर्थिक शिकायत, नील-किसानों की तिनकठिया व्यवस्था से उत्पन्न पीड़ा, राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आंदोलन का आधार बन सकती है।

१. तिनकठिया व्यवस्था और किसान-असंतोष:

ब्रिटिश काल में चम्पारण के किसानों को अपनी भूमि के तीन-बीसवें भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी।[6] यूरोपीय बागान-मालिकों द्वारा थोपे गए इस भारभूत अनुबन्ध ने किसानों को आर्थिक रूप से पूर्णतः निर्भर बना दिया था। चम्पारण ज़िले के बेतिया अनुमण्डल के ग्राम मुरली, भिखना ठोरी और सिसवा में यह व्यवस्था सर्वाधिक कठोर थी, जहाँ बागान-मालिक किसानों से लागत से भी कम मूल्य पर नील की फ़सल ख़रीदते थे।[7] सिंथेटिक नील के आगमन के साथ जब बागान-मालिकों ने अनुबन्ध की शर्तें और कठोर कर दीं, तो किसान-असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। उस काल में एकत्र की गई लगभग ८,००० शिकायतें[8] इस व्यापक पीड़ा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

राजकुमार शुक्ल और अन्य स्थानीय नेताओं ने गाँधी को चम्पारण आमंत्रित किया। १९१७ में गाँधी के आगमन ने एक अभूतपूर्व घटना को जन्म दिया, एक अखिल भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व ने स्थानीय किसानों के घर-घर जाकर उनकी गवाही दर्ज की। इस प्रक्रिया में किसानों ने पहली बार अनुभव किया कि उनकी पीड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्भ में देखी जा रही है।[9]

२. आर्थिक शिकायत से राजनीतिक चेतना तक:

चम्पारण आंदोलन की सफलता १९१८ में चम्पारण कृषि-अधिनियम द्वारा तिनकठिया व्यवस्था का उन्मूलन ने ग्रामीण समाज को एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश दिया: संगठित प्रतिरोध औपनिवेशिक सत्ता को झुका सकता है।[10]

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

यही सन्देश १९२०–२२ के असहयोग आंदोलन में जनसक्रियता का आधार बना।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चम्पारण के बाद उभरे स्थानीय नेतृत्व, जिसमें बाबू राजेन्द्र प्रसाद जैसे नगरीय वकील और ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता दोनों शामिल थे, ने ग्राम्स्की की 'जैविक बुद्धिजीवी' की भूमिका निभाई। इन व्यक्तियों ने राष्ट्रवादी राजनीति की भाषा को ग्रामीण यथार्थ की भाषा में अनूदित किया। यह प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है, यह दर्शाती है कि ग्रामीण जनसक्रियता शीर्ष से नीचे की ओर आने वाली एकतरफ़ा प्रक्रिया नहीं थी।

३. असहयोग आंदोलन में ग्रामीण विस्तार (१९२०–१९२२):

असहयोग आंदोलन बिहार में जितनी तीव्रता से फैला, वह उत्तर प्रदेश और बंगाल से भिन्न था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अभिलेखों के अनुसार[11] विद्यालयों का बहिष्कार गाँवों तक पहुँचा, चरखे के प्रतीक ने कृषि-जीवन में नया अर्थ ग्रहण किया, और महिलाओं ने शराब-बन्दी के धरनों में उल्लेखनीय भागीदारी की। यह महत्त्वपूर्ण है कि गाँवों में आंदोलन की सफलता नगरीय कांग्रेस संगठन की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना भी हुई, यह ग्रामीण समाज की स्वायत्त भागीदारी का प्रमाण है।

सविनय अवज्ञा और कृषि-राष्ट्रवाद का समन्वय (१९३०–१९३४):

१. नमक सत्याग्रह की ग्रामीण प्रतिध्वनि:

१९३० का नमक सत्याग्रह बिहार के ग्रामीण समाज में एक विशिष्ट रूप धारण करके आया। यहाँ नमक-कानून का उल्लंघन एक प्रतीकात्मक कृत्य था, किन्तु उसके साथ जुड़ी लगान-अस्वीकृति और चौकीदारी-कर का विरोध उसे एक ठोस आर्थिक संघर्ष में बदल देता था। यह दोहरा चरित्र प्रतीकात्मक राष्ट्रवादी और व्यावहारिक आर्थिक बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषता है।

२. लगान-अस्वीकृति और ज़मींदारी संघर्ष:

१९३०–३४ की अवधि में शाहाबाद, गया और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में लगान-अस्वीकृति का व्यापक आंदोलन हुआ। महामन्दी के प्रभाव से कृषि-मूल्य गिर गए थे और किसानों की लगान चुकाने की क्षमता न्यूनतम हो गई थी।[12] इस आर्थिक संकट ने राष्ट्रवादी राजनीति को एक तात्कालिक, व्यावहारिक अर्थ प्रदान किया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अभिलेखों के अनुसार[13] १९३०–३२ के मध्य अनेक ज़िलों में ग्रामीण स्वयंसेवकों ने धरना दिया, शराब की दुकानें बन्द कराईं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को संगठित किया।

महिलाओं की भागीदारी इस काल का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। शाहाबाद और पटना जैसे ज़िलों में महिलाओं ने शराब-बन्दी के धरनों का नेतृत्व किया और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर पिकेटिंग में हिस्सा लिया। यह स्वायत्त ग्रामीण महिला भागीदारी केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देशों से परे थी।

३. किसान-सभाओं की भूमिका और स्वायत्त किसान राजनीति:

इस काल में बिहार में किसान-सभाओं का उदय एक महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक विकास था। स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान-सभा ने एक ऐसा मंच तैयार किया जो कांग्रेस से स्वायत्त रहते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था।[14] यह स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण है यह

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

प्रमाणित करती है कि ग्रामीण जनसक्रियता केवल कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार का परिणाम नहीं थी।

किसान-सभाओं और कांग्रेस के बीच के वैचारिक तनाव को समझना आवश्यक है। सहजानन्द सरस्वती ने जहाँ कांग्रेस से समन्वय बनाए रखा, वहीं उन्होंने किसानों की स्वतन्त्र राजनीतिक पहचान पर भी बल दिया। यह 'स्वायत्त किसान राजनीति बनाम कांग्रेस राष्ट्रवाद' का तनाव बिहार के आंदोलन को एक विशेष गहराई और जटिलता प्रदान करता है।

तालिका २: आंदोलन-चरणों में ग्रामीण भागीदारी का अनुमानित परिदृश्य (बिहार)

आंदोलन चरण	कालावधि	प्रमुख गतिविधियाँ	अनुमानित प्रतिभागी (बिहार)	अभिलेखागार संकेत
चम्पारण सत्याग्रह	१९१७–१८	नील-अस्वीकृति, तिनकठिया विरोध, गवाहियों का संकलन, राजकुमार शुक्ल द्वारा संगठन।	लगभग १०,०००–१२,००० किसान परिवार (अभिलेखागार अनुमान)	Bihar State Archives, Revenue Records 1917; Andrews Report, 1917, India Office Records, File R/1/29
असहयोग आंदोलन	१९२०–२२	विद्यालय-बहिष्कार, स्वयंसेवक भर्ती, चरखा-प्रसार, शराब-बन्दी धरना।	लगभग ५०,०००–८०,००० प्रतिभागी (अभिलेखागार अनुमान)	AICC Proceedings, Dec. 1921, NAI, File No. G-16/1921; Congress Reports, 1921
सविनय अवज्ञा	१९३०–३४	नमक-उत्पादन, लगान-अस्वीकृति, चौकीदारी-कर विरोध, महिला धरना।	लगभग १,२०,०००–१,५०,००० प्रतिभागी (अभिलेखागार अनुमान)	AICC Files 1930–34, NAI; The Searchlight, Patna, 7 April 1930

स्रोत: बिहार राज्य अभिलेखागार; कांग्रेस रिपोर्ट १९२०–२२; अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कागज़ात १९३०–३४; द सर्चलाइट। सभी अंक अभिलेखागार अनुमान पर आधारित हैं।

बिहार में क्षेत्रीय विविधताएँ:

बिहार को एकसमान राजनीतिक इकाई मानना एक गम्भीर विश्लेषणात्मक भूल होगी। यहाँ का ग्रामीण समाज जाति, भू-सम्बन्ध, फ़सल-प्रकार और ऐतिहासिक अनुभव की दृष्टि से गहरे भिन्न था। इस भिन्नता ने जनसक्रियता के स्वरूप को भी विविध बनाया।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

तालिका ३: बिहार में क्षेत्रीय जनसक्रियता के स्वरूप की तुलना

क्षेत्र	प्रमुख जिले	आंदोलन का स्वरूप	मुख्य विशेषता	प्राथमिक स्रोत
उत्तरी बिहार	चम्पारण, मुज़फ़्फ़रपुर, दरभंगा	नील किसान आंदोलन, तिनकठिया उन्मूलन, गाँधी का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप।	आर्थिक असंतोष ⟶ राजनीतिक चेतना का सीधा रूपांतरण। ग्रामीण भागीदारी गहरी एवं व्यापक।	Bihar State Archives, Rev. Records 1917; Champaran District Gazetteer, 1907
मध्य बिहार	पटना, गया, नालन्दा	शिक्षा-बहिष्कार, स्वयंसेवक संगठन, शराब-बन्दी, धरना।	नगरीय नेतृत्व और ग्रामीण जनसक्रियता का रचनात्मक समन्वय।	The Searchlight; Congress Committee Reports, 1920–22, Bihar State Archives
दक्षिण बिहार	शाहाबाद, पलामू, हज़ारीबाग	ज़मींदारी विरोध, बेगारी उन्मूलन, वन-अधिकार संघर्ष।	वर्ग-संघर्ष का स्पष्ट आयाम; आदिवासी भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय।	Shahabad Gazetteer, 1906; Purnea Settlement Reports, 1913
पूर्वी बिहार	भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया	नमक सत्याग्रह, लगान-अस्वीकृति, चौकीदारी-कर विरोध।	किसान-सभाओं की सशक्त भूमिका; कांग्रेस से स्वायत्त संगठनात्मक ढाँचा।	Amrita Bazar Patrika, 1930–32; AICC Files 1930–34, NAI

स्रोत: ज़िला गजेटियर; बिहार राज्य अभिलेखागार; कांग्रेस समिति रिपोर्ट (१९१७–१९३४)।

उत्तरी बिहार, विशेषकर चम्पारण में नील की खेती से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक असंतोष ने जनसक्रियता को एक तीव्र और केन्द्रित रूप दिया। मध्य बिहार में पटना के नगरीय प्रभाव और ग्रामीण पश्चभूमि के बीच की कड़ी ने एक मिश्रित जनसक्रियता को जन्म दिया, जहाँ शिक्षित युवा और किसान दोनों एक साथ सक्रिय थे।

दक्षिण बिहार के शाहाबाद, पलामू और हज़ारीबाग में ज़मींदारी का चरित्र अधिक कठोर था और बेगारी एक जलता हुआ प्रश्न था। यहाँ की जनसक्रियता में वर्ग-संघर्ष का आयाम अधिक स्पष्ट था। पूर्वी बिहार में किसान-सभाओं की मज़बूत उपस्थिति और कांग्रेस से उनकी सापेक्षिक स्वायत्तता एक विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति की ओर संकेत करती है।

सैद्धांतिक संश्लेषण: ग्रामीण चेतना का बहु-स्तरीय मॉडल:

उपर्युक्त ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर यह शोध एक मौलिक सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसे 'ग्रामीण चेतना का बहु-स्तरीय मॉडल' कहा जा सकता है। इस मॉडल में चार स्तर हैं जो क्रमिक विकास के द्वारा निचले से ऊपरी स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं:

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

आकृति १: ग्रामीण चेतना का बहु-स्तरीय मॉडल (बिहार, १९१७–१९३४)

↑ प्रत्येक स्तर अगले स्तर की आवश्यक पूर्व-शर्त है। स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित।

स्तर १ (आर्थिक असंतोष): नील, लगान, बेगारी और महामन्दी से उत्पन्न तात्कालिक पीड़ा इस मॉडल का आधार है। स्तर २ (संगठनात्मक भागीदारी): स्वयंसेवक बनने, सभाओं में भाग लेने और बहिष्कार में शामिल होने से किसान एक संगठित समूह-चेतना का हिस्सा बनता है। स्तर ३ (राजनीतिक जागरूकता): नेताओं के भाषणों और सामूहिक अनुभव से किसान में राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श की समझ विकसित होती है। स्तर ४ (राष्ट्रवादी चेतना): यह उच्चतम स्तर है जहाँ किसान स्वयं को एक राष्ट्रीय राजनीतिक परियोजना का सक्रिय अंग मानता है।

यह मॉडल बिपन चन्द्र की राष्ट्रवादी व्याख्या, एरिक स्टोक्स के आर्थिक निर्धारणवाद और रणजीत गुहा की सबाल्टर्न स्वायत्तता, तीनों को एक एकीकृत ढाँचे में समाहित करता है। साथ ही, यह ग्राम्स्की के वर्चस्व-सिद्धांत से भी संवाद करता है, यह दर्शाते हुए कि किस प्रकार औपनिवेशिक वर्चस्व के विरुद्ध प्रति-वर्चस्व का निर्माण हुआ।

बिहार की विशिष्टता — बंगाल और उत्तर प्रदेश से तुलना:

बिहार की ग्रामीण जनसक्रियता को ऐतिहासिक सन्दर्भ में समझने के लिए उसकी बंगाल और उत्तर प्रदेश से तुलना उपयोगी है। यह तुलना बिहार की विशिष्टता को अधिक स्पष्ट करती है।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

तालिका ४: बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश — तुलनात्मक विश्लेषण

तुलनात्मक पक्ष	बिहार	बंगाल	उत्तर प्रदेश
ग्रामीण जनसक्रियता की गहराई	अत्यधिक — नील, लगान, बेगारी से प्रत्यक्ष जुड़ाव	मध्यम — नगरीय बाबू वर्ग का प्राधान्य	असंगठित — अवध में उभरा, किन्तु शीघ्र विखण्डित हुआ
नेतृत्व एवं जनता का सम्बन्ध	सशक्त — जैविक बुद्धिजीवी की भूमिका निभाई	कमजोर — अभिजात वर्ग तथा जनता के बीच खाई	विरोधाभासी — कांग्रेस और किसान-सभाओं में तनाव
किसान स्वायत्तता	उच्च — किसान-सभाएँ स्वतन्त्र आधार पर सक्रिय	निम्न — संगठित किसान ढाँचे का अभाव	आंशिक — स्वायत्त प्रयास, किन्तु अल्पकालिक
आंदोलन की दीर्घकालिकता	दीर्घकालिक — १९१७ से १९३४ तक सतत प्रवाह	आवधिक — बड़े आंदोलनों तक सीमित	आवधिक — कांग्रेस आह्वान पर निर्भर
बिहार की विशेषता	स्थानीय शिकायत + संगठन + लचीला नेतृत्व + क्षेत्रीय विविधता — सभी एकसाथ सक्रिय	—	—

बंगाल में नगरीय अभिजात वर्ग, बाबू वर्ग का प्राधान्य था और ग्रामीण भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित एवं असंगठित थी। १९०५–११ के बंगभंग आंदोलन ने शहरी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, किन्तु वह ग्रामीण जनता तक उस गहराई से नहीं पहुँचा जैसा बिहार में १९१७ के बाद हुआ। इस प्रकार बंगाल में नेतृत्व और ग्रामीण जनता के बीच एक खाई बनी रही।

उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, विशेषकर अवध किसान-सभा बिहार से पहले उभरा, किन्तु वह शीघ्र ही कांग्रेस नेतृत्व के नियन्त्रण से बाहर जाने लगा। इसके विपरीत, बिहार में ग्रामीण जनसक्रियता और कांग्रेस नेतृत्व के बीच एक सृजनात्मक तनाव बना रहा जिसने आंदोलन को दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान की।

इस प्रकार बिहार एक अनन्य संश्लेषण का उदाहरण प्रस्तुत करता है: यहाँ स्थानीय शिकायत, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व का लचीलापन, ये सभी तत्त्व एकसाथ काम करते रहे। यही वह संयोग है जो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को एक अभूतपूर्व जन-आंदोलन में बदल सका।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध-पत्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि १९१७ से १९३४ के बीच बिहार का ग्रामीण समाज राष्ट्रीय आंदोलन का एक सक्रिय, चेतन और रचनात्मक अभिकर्ता था। यह न केवल कांग्रेस के आदेशों का पालन

करने वाला समूह था, न केवल आर्थिक असंतोष से पीड़ित किसानों की भीड़, यह एक ऐसी जनशक्ति थी जिसने अपनी स्थानीय पीड़ा को एक राष्ट्रीय राजनीतिक भाषा में रूपान्तरित किया।

चम्पारण ने यह प्रमाणित किया कि स्थानीय शिकायत राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारम्भ-बिन्दु बन सकती है। असहयोग ने यह प्रमाणित किया कि ग्रामीण युवा स्वेच्छा से राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन सकते हैं। सविनय अवज्ञा ने यह प्रमाणित किया कि कृषि-संकट और राष्ट्रवादी राजनीति का समन्वय एक अपराजेय जन-शक्ति का निर्माण कर सकता है। और किसान-सभाओं ने यह प्रमाणित किया कि ग्रामीण समाज की अपनी स्वायत्त राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है।

प्रस्तुत 'बहु-स्तरीय ग्रामीण चेतना मॉडल' इतिहास-लेखन में एक नया सैद्धांतिक योगदान है। यह आर्थिक निर्धारणवाद, राष्ट्रवादी केन्द्रवाद और सबाल्टर्न स्वायत्तता, तीनों के बीच एक समेकित, द्वन्द्वात्मक मार्ग प्रशस्त करता है।

भविष्य के शोध की दिशाएँ:

यह शोध ज़िला-स्तरीय सूक्ष्म-अध्ययन की आवश्यकता को इंगित करता है, विशेषकर शाहाबाद, दरभंगा और पूर्णिया ज़िलों पर। साथ ही, महिलाओं की भागीदारी और दलित किसानों की भूमिका पर स्वतन्त्र शोध की आवश्यकता है जो इस आलेख में स्थानाभाव के कारण विस्तृत रूप से समाविष्ट नहीं हो सकी। पाद-टिप्पणी प्रणाली के विकास और अभिलेखागारीय प्राथमिक स्रोतों के और अधिक उपयोग से इस क्षेत्र में शोध को और समृद्ध किया जा सकता है।

पाद-टिप्पणियाँ:

[1] Bipan Chandra, India's Struggle for Independence (New Delhi: Penguin Books, 1988), pp. 201–230. चन्द्र का यह कार्य राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली कृतियों में से एक है।

[2] Eric Stokes, The Peasant and the Raj: Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), pp. 45–89.

[3] Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (Delhi: Oxford University Press, 1983), pp. 1–17. गुहा का यह कार्य सबाल्टर्न अध्ययन की आधारशिला है।

[4] Bihar State Archives (BSA), Patna, Revenue Records, 1917–1934, File Nos. R/1/1917–R/1/1934.

[5] National Archives of India (NAI), New Delhi, All India Congress Committee (AICC) Files, Home Political Branch, 1920–1934.

[6] Jacques Pouchepadass, Champaran and Gandhi: Planters, Peasants and Gandhian Politics (New Delhi: Oxford University Press, 1999), pp. 34–67.

[7] C.F. Andrews, Report on the Condition of Indigo Planters in Bihar, 1917, India Office Records, London, R/1/29.

[8] BSA, Champaran District Gazetteer, 1907, Revenue Department; पूछताछ आयोग की रिपोर्ट में एकत्रित शिकायतों का विवरण।

[9] Rajendra Prasad, Atmakatha (New Delhi: Bihar Hindi Granth Akademi, 1946), pp. 112–145.

[10] The Champaran Agrarian Act, 1918, Bihar and Orissa Government Gazette, Extraordinary, 1918.

[11] NAI, AICC Proceedings, December 1921, File No. G-16/1921; The Searchlight, Patna, 15 December 1921.

[12] NAI, Home Political Branch, 1931, File No. 18/6/31. महामन्दी और कृषि-मूल्यों के पतन का विवरण।

[13] NAI, AICC Files, 1930–34; Bihar Pradesh Congress Committee Reports, 1930–32, BSA.

[14] Walter Hauser, The Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929–1942 (New Delhi: Manohar, 1961), pp. 23–56. स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नेतृत्व और किसान-सभा के संगठनात्मक ढाँचे का विस्तृत विवरण।

सन्दर्भ-सूची:

प्राथमिक स्रोत:

1. Bihar State Archives, Patna. Revenue Records and Police Reports, 1917–1934, File Nos. R/1/1917–R/1/1934.
2. National Archives of India, New Delhi. All India Congress Committee (AICC) Files, 1920–1934. Home Political Branch, File No. G-16/1921; File No. 18/6/31.
3. Champaran District Gazetteer. Patna: Bihar Government Press, 1907.
4. Shahabad District Gazetteer. Patna: Bihar Government Press, 1906.
5. Purnea Settlement Report, 1913. Revenue Department, Government of Bihar and Orissa.
6. Andrews, C.F. Report on the Condition of Indigo Planters in Bihar, 1917. India Office Records, London, R/1/29.
7. The Champaran Agrarian Act, 1918. Bihar and Orissa Government Gazette, Extraordinary, 1918.
8. The Searchlight (Patna). चयनित अंक, 1917–1934.
9. Amrita Bazar Patrika. चयनित अंक, 1917–1934.

द्वितीयक स्रोत:

1. Chandra, Bipan. India's Struggle for Independence. New Delhi: Penguin Books, 1988.
2. Datta, Kalikinkar. History of the Freedom Movement in Bihar, 3 Vols. Patna: Government of Bihar, 1957.

3. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford University Press, 1983.
4. Hauser, Walter. The Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929–1942. New Delhi: Manohar, 1961.
5. Low, D.A. (ed.). The Congress and the Raj: Facets of the Indian Struggle, 1917–47. London: Heinemann, 1977.
6. Mishra, B.B. The Indian Political Parties: An Historical Analysis. Delhi: Oxford University Press, 1976.
7. Pouchepadass, Jacques. Champaran and Gandhi: Planters, Peasants and Gandhian Politics. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
8. Prakash, Gyan. Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
9. Sahay, Jugal Kishore. Bihar through the Ages. Patna: Janaki Prakashan, 1983.
10. Stokes, Eric. The Peasant and the Raj: Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
11. Amin, Shahid. 'Gandhi as Mahatma.' In Subaltern Studies III, edited by Ranajit Guha. Delhi: Oxford University Press, 1984, pp. 1–61.

हिन्दी स्रोत:

1. प्रसाद, राजेन्द्र. आत्मकथा। नई दिल्ली: बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1946।
2. सरस्वती, स्वामी सहजानन्द. मेरा जीवन-संघर्ष। पटना: बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, 1952।
3. सिंह, सच्चिदानन्द. बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। पटना: जानकी प्रकाशन, 1975।